1	2	3	4	5
22.	Tamilnadu	135.06	140.28	145.06
23.	Tripura	2.75	3.04	3.10
24.	Uttar Pradesh	78.42	76.86	82.37
25.	West Bengal	181.19	132.71	117.51
	Total :	1,109.53	1,331.99	1,335.99

Statement-II

Average Monthly Rents paid in the Metropolitan Cities

(Figures in lakhs of Rs.)

Name of the Metropolitan city	Average monthly rent paid in 1987-88
Bombay	22.42
Calcutta	6.09
Delhi	3.90
Madras	2.91

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के लिए राज सहायता का उपबंध

3690. **श्री राम नरेश यादव :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा खादी ग्राम उद्योगों को प्रति वर्ष राज सहायता दी जाती है, यदि हां, तो गत तीन वर्षों में वर्षवार कितनी-कितनी राशि दी गयी है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि खादी ग्रामोद्योग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों की स्थापना करने के लिये प्रोत्साहन दिया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो अब तक किस प्रकार के कुटीर उद्योग स्थापित किये गये हैं ; और पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे उद्योग स्थापित करने के लिये प्रोत्साहन देने हेतु वर्षवार कुल कितनी रकम खर्च की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) सरकारी खादी तथा ग्राम उद्योग आयोग को सरकारी ऋणों पर ब्याज के बदले में राजसहायता देती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान दी गयी राजसहायता की कुल राशि इस प्रकार है :-

(करोड़ रु.में)

वर्ष	राजसहायता की राशि
1985-86	42.00
1986-87	44.00
1987-88	--*

*वर्ष 1987-88 के दौरान राजसहायता के लिये 45.00 करोड़ रु० का प्रावधान किया गया था किन्तु खादी और ग्रामोद्योग आयोग को कोई राशि जारी नहीं की गयी थी क्योंकि उक्त प्रावधान पिछड़े क्षेत्रों में नये औद्योगिक एककों को राजसहायता देने के लिये दिशान्तरित कर दिये गये थे।

(ख) जी, हां, ।

(ग) खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने खादी और 26 ग्रामोद्योग लगाये हैं। (ब्यौरे विवरण में दिये गये है) ।

(नीचे देखिये) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये खादी और ग्रामोद्योग आयोग को जारी की गयी राशि से संबंधित ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :–

खादी और ग्रामोद्योग आयोग को सरकार द्वारा जारी की गई राशि (लाख रु० में)

वर्ष	योजनागत			योजनेतर				
	खादी अनुदान	ग्रामोद्योग अनुदान	खादी और ग्रामोद्योग के लिये राज-सहायता	उपयोग	खादी अनुदान	खादी और	उपयोग	कुल योग ग्रामोद्योग के लिये राज-सहायता
1985–86	1000	800	800	2600	2400	3400	3800	8400
1986–87	1898	700	1000	3598	2400	9400	3900	9398
1987–88	2400	900	--	3300	2400	--	2400	5700

विवरण

खादी और ग्रामोद्योग आयोग की परिसीमा में आने वाले ग्रामोद्योगों की सूची

1. मधुमक्खी पालन ।
2. कुटीर माचिस उद्योग, आतिशबाजी और अगरबत्तियों का उत्पादन ।
3. कुटीर मृत्तिका-भाण्ड उद्योग ।
4. कुटीर साबुन उद्योग ।
5. खालों और चर्मों को उधेड़ना, परिस्करण, कमाना तथा इससे संबंधित सहायक उद्योग एवं कुटीर चमड़ा उद्योग ।
6. घानी तेल उद्योग ।
7. हस्तनिर्मित कागज ।
8. गन्ने से गुड़ बनाना और खण्डसारी बनाना ।
9. ताड़ से गुड़ बनाना और अन्य ताड़-उत्पादन उद्योग ।
10. "खाद्यान्नों, दालों, मसालों, अचारों, मसालों इत्यादि का प्रसंस्करण, पैकिंग और विपणन" ।
11. गाय के गोबर और अन्य रद्दी उत्पादों (जैसे मरे हुये जानवरों के मांस गोबर खाद इत्यादि) से खाद और मैथेन गैस बनाना और उपयोग करना ।
12. चूने का पत्थर, चूना पट्टिका तथा चूने के अन्य उत्पादों के उद्योग ।
13. लाख विनिर्माण ।
14. औषधीय कार्यों के लिये वन्य पौधों व फलों का एकत्रीकरण ।
15. आचार सहित फल तथा वनस्पति प्रसंस्करण परिरक्षण और डिब्बाबंदी।
16. बांस तथा वेंत कार्य ।
17. लोहारी ।

18. बढ़ईगिरी ।

19. कयर के अलावा फाइबर ।

20. एल्युमिनियम से घरेलू बर्तनों का विनिर्माण ।

21. कत्था विनिर्माण ।

22. गौंद शल का विनिर्माण ।

23. लोक-वस्त्र कपड़े का विनिर्माण ।

24. "पोलीवस्त्र" जिसका अर्थ है कि कोई भी वह कपड़ा जिसे भारत में हथकरघे पर बुना गया है और जिसके धागे की कताई भारत में हाथ से की गई हो और यह धागा मानव-निर्मित फाइबर और सूत, रेशम या ऊन अथवा इनमें से किन्हीं दो के या इन सबके मिश्रण से बना हो या जिसका धागा भारत में हाथ से कते हुये मानव निर्मित फाइबर धागे और भारत में हाथ से कते हुये सूती, रेशमी या ऊनी धागों या इनमें से किन्हीं दो के अथवा सभी धागों के मिश्रण से बना हो ।

25. मक्का और मोटे अनाज का प्रसंस्करण ।

26. रबड़ की वस्तुओं (डिम्पड लेटेक्स प्रोडक्टस) का विनिर्माण ।

Training Programme organised through the Rural Electrification Corporation

3691. SHRI S. S. AHLUWALIA: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether any training programme is being organised through the REC (Rural Electrification Corporation) for officers of State Electricity Boards, State Governments and Banks to guide farmers in choosing and installing properly matched and efficient pumping system;

(b) if so, what are the salient features of the programme and the names of the States where such programme has been organised;

(c) whether Government have any monitoring system to see that the officers of State Governments, State Electricity Boards and Banks who have been guided by REC are transmitting their guidance to the farmers in a proper manner; and

(d) if so, what are the details in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF POWER IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI KALPNATH RAI): (a) Yes, Sir.

(b) The Programme envisages imparting training in the matter of installation of efficient irrigation pumping systems for 900 supervisory and field level officers of State Electricity Boards, State Governments and Banks etc. So far 13 programmes covering 286 officers have been conducted at Hyderabad (Andhra Pradesh) and Nasik (Maharashtra) Each of these programmes included a cross section of participants drawn from different States.

(c) The Training Programme has been very well received by the participants and their sponsors.

(d) and (e) The sponsoring agencies are advised to depute only the concerned field officers to attend the training programmes so as to ensure that on getting trained, they are utilised for dissemination of knowledge and transmitting guidance to the farmers.

Chartering of helicopter service by ONGC for offshore operation

3692. SHRI S. S. AHLUWALIA:

SHRI SHIV PRATAP MISHRA:

Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that ONGC are no more chartering helicopter services from abroad for its offshore operations and instead utilising the services of Pawan Hans; if so, since when;

(b) how many incidents of helicopter accidents have occurred year-wise during